भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1251
03 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

झींगा उद्योग पर परजीवियों का प्रभाव

1251. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परजीवियों और इसी प्रकार के विभिन्न संक्रमणों के कारण पूरे भारत में झींगा किसानों को हुए नुकसान के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण /अध्ययन / अनुसंधान कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत भर में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश और विशेष रूप से एलुरु जिले में झींगा किसानों को हुए नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश और विशेष रूप से एलुरु जिले में झींगा किसानों को हुए नुकसान को कम करने के लिए शुरू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान विशेषकर आन्ध्र प्रदेश और विशेष रूप से एलुरु जिले में उपर्युक्त योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों के प्रयोजनार्थ आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या और

(ङ) क्या सरकार ने परजीवियों/संक्रमणों के कारण झींगा किसानों को होने वाले नुकसान के मुद्दे के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए कोई गतिविधि / अभियान चलाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने बताया है कि आईसीएआर-केंद्रीय खारा जलकृषि संस्थान (आईसीएआर-सीआईबीए), चेन्नई ने 2021 से 2023 के दौरान जलीय कृषि में बीमारियों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान पर एक अध्ययन किया । कुल मिलाकर, देश में विभिन्न रोगों के कारण लगभग 2.1 लाख टन उपज का नुकसान हुआ । विभिन्न झींगा (श्रिम्प) रोगों के कारण अनुमानित वार्षिक नुकसान 7112 करोड़ रुपये था, जिसमें एंटरोसाइटोजून हेपेटोपेनाई (ईएचपी) के कारण 3,977 करोड़ रुपये का नुकसान, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (डब्ल्यूएसएसवी) के कारण 1670 करोड़ रुपये का नुकसान और अन्य बीमारियों के कारण 1465 करोड़ रुपये का नुकसान शामिल है।

(ख): आईसीएआर- केंद्रीय खारा जलकृषि संस्थान द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख झींगा उत्पादक राज्यों में झींगा पालन में हुए नुकसान का ब्यौरा (i) आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश में झींगा रोगों के कारण उत्पादन का कुल अनुमानित नुकसान 3,975 करोड़ रुपये था, जिसमें ईएचपी के कारण 2275 करोड़ रुपये, डब्ल्यूएसएसवी के कारण 802 करोड़ रुपये और अन्य रोगों के कारण 326 करोड़ रुपये शामिल हैं, (ii) तमिलनाडु: तमिलनाडु में नुकसान 466 करोड़ रुपये था, जिसमें ईएचपी के कारण 265 करोड़ रुपये, डब्ल्यूएसएसवी के कारण 127 करोड़ रुपये और अन्य रोगों के कारण 73 करोड़ रुपये शामिल हैं और (iii) गुजरात: नुकसान 266 करोड़ रुपये था, जिसमें ईएचपी के कारण 110 करोड़ रुपये, डब्ल्यूएसएसवी के कारण 123 करोड़ रुपये और अन्य रोगों के कारण 32 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सभी तटीय राज्यों सहित देश भर में आईसीएआर मात्स्यिकी संस्थानों, मात्स्यिकी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की 31 प्रयोगशालाओं के माध्यम से जलीय जीव रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम / नेशनल सरवेलेन्स प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डीसीसेस (एनएसपीएएडी) को कार्यान्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम चिंता के प्रमुख झींगा रोगों की एक्टिव और पैसिव निगरानी, क्लीनिकल सेवाएँ प्रदान करने और रोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन रणनीतियों का प्रचार करने के लिए शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश एनएसपीएएडी कार्यक्रम में प्रमुख साझेदार राज्यों में से एक है और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लैबोरेटोरीस (एनएबीएल) के साथ एकरेडिटेड राज्य मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (एसआईएफटी), काकीनाडा आंध्र प्रदेश में परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है, जो समय-समय पर सभी जिलों से नमूने एकत्र करती है और उनमें सूचीबद्ध रोगों की उपस्थिति के लिए परीक्षण करती है तथा रोगों की उपस्थिति की रिपोर्ट आईसीएआर-राष्ट्रीय मात्स्यिकी आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (आईसीएआर-एनबीएफजीआर) को सौंपती है । इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया कि राज्य में 35 प्रयोगशालाएं स्थापित हैं, जिनमें एलुरू जिला भी शामिल है, जो जल, मिट्टी और कलचर्ड जीवों के नमूने एकत्र करती हैं और समय-समय पर रोगों की उपस्थिति के लिए उनका परीक्षण करती हैं, और क्षेत्रीय स्तर के मात्स्यिकी अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्रीय दौरे और झींगा तालाबों का आवधिक निरीक्षण करते हैं और संज्ञान होने पर विशिष्ट रोगों की पहचान करते हैं और उपचार सुझाते हैं।

(घ): आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि एनएसपीएडी कार्यक्रम और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश में झींगा किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए 27.96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 27.77 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह भी बताया है कि एलुरु जिले के भीमाडोल में 27.00 लाख रुपये के निवेश से एक एकीकृत जल प्रयोगशाला स्थापित की गई है और एलुरु और कैकलुरु में दो मौजूदा प्रयोगशालाओं के अलावा, तीनों प्रयोगशालाएँ काम कर रही हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार एलुरु जिले में मत्स्य सागु बाड़ी और प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के तहत 1.43 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है ।

(ड.): आईसीएआर-सीआईबीए ने झींगा फार्मों में नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और 2024 के दौरान चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में झींगा पालन में रिस्क मेनेजमेंट सर्वे और नुकसान का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं । हाल ही में, आईसीएआर-सीआईबीए ने विभिन्न बीमारियों के कारण होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्टस जारी किए। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ने आईसीएआर-सीआईबीए के तकनीकी मार्गदर्शन के साथ रोगों और मौसम के जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए बीमा उत्पाद जारी किए हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने झींगा फार्मों में बीमारियों के प्रबंधन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे (i) रोग की घटना के मुद्दों और परजीवी/संक्रमण के कारण झींगा किसानों को होने वाले संभावित नुकसान और उपचारात्मक उपायों के बारे में जलीय कृषि किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान, (ii) जलीय कृषि किसानों को विस्तार सेवाएं देने तथा गांव स्तर पर विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए इन केंद्रों में 750 ग्राम मात्स्यिकी सहायक / विल्लेज फिशेरी एसिस्टेंट्स (वीएफए) तैनात किए गए हैं, (iii) मत्स्य सागु बाड़ी: यह "एक्का फार्मर्स फील्ड स्कूल" है और यह जलीय कृषि किसानों को विस्तार सेवाएं और फसल सलाह प्रदान करने और क्षेत्र में ज्ञान और तकनीकी कौशल का प्रसार करने की एक पहल है। आयोजित कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी नियमित रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म (ई-मत्स्यकर पोर्टल) के माध्यम से की जाती है और (iv) इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर: किसानों को सलाह प्रदान करने और विशेषज्ञों द्वारा मछुआरों के प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 63 तकनीकी अधिकारियों के साथ एक समर्पित इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, और सूचना प्रसार के लिए बैक एंड सपोर्ट के लिए आईसीएआर मात्स्यिकी संस्थानों, मात्स्यिकी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से विशेषज्ञों का एक पैनल भी पहचाना गया है।

****